मल्टी माडल कनेक्टिविटी के लिए इन्फ्रा बांड से रकम जुटाएगा यीडा

बांड से दस हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: यीडा क्षेत्र में मल्टी माडल कनेक्टिविटी परियोजना के लिए यमुना प्राधिकरण इन्फ्रा बांड लाने की तैयारी कर रहा है। इन्फ्रा बांड से कम से कम दस हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है। प्राधिकरण को परियोजनाओं में अपनी अंशधारिता के लिए तकरीबन 20 से 22 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। इन्फ्रा बांड के लिए केयर एजेंसी से कराई गई रेटिंग में प्राधिकरण को बीबीबी एलस रेटिंग मिली है।

यीडा में विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है। विकास की गति को जारी रखने के लिए प्राधिकरण को रकम की जरूरत है। विकास परियोजनाओं से लेकर जमीन अधिग्रहण में प्राधिकरण को हजारों करोड़ रुपये की जरूरत है। पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने यीडा को ब्याज मुक्त 3,000 करोड़ रुपये का ऋण दिया है, इसके अतिरिक्त यीडा ने ऋण के लिए हुडको से भी अनुबंध किया है। लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण यीडा क्षेत्र में मल्टी माडल कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं पर खास जोर है। दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रेलवे रूट को जोड़ने के लिए बनने वाले नए रूट, हाइ स्पीड रेल, रैपिड रेल, मेट्रो, पीआरटी, पाड टैक्सी आदि मल्टी माडल कनेक्टिविटी परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए यीडा को बड़ी रकम की जरूरत होगी। इसलिए यीडा ने इन्फ्रा बांड के जरिये रकम जुटाने का निर्णय किया है। इसके लिए पिछले करीब दो साल से यीडा प्रयास कर रहा है, लेकिन रेटिंग अच्छी न होने के कारण इन्फ्रा बांड के फैसले का आगे बढ़ाना पड़ा। केयर एजेंसी से कराई गई रेटिंग में बीबीबी एलस मिलने के बाद यीडा ने इन्फ्रा बांड जारी करने का फैसला किया है। सीईओ डा. अरुणवीर सिंह का कहना है कि इन्फ्रा बांड से जुटाई गई रकम को यीडा केवल मल्टी माडल कनेक्टिविटी परियोजना में ही खर्च करेगा। 10 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार के पैनल में शामिल 12 कंपनियों में से एक का चयन ट्रांजिक्शन एडवाजर के रूप में करेंगे। कंपनियों को प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

यमुना प्राधिकरण कार्यालय●

12 कंपनियों में से एक का चयन ट्रांजिक्शन एडवाजर के रूप में किया जाएगा

3,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया है प्रदेश सरकार ने यीडा को

एक हजार करोड़ से अधिक सर प्लस

यीडा के पास मौजूदा समय में एक हजार करोड़ से अधिक रकम मौजूद है। प्राधिकरण ने विभिन्न स्रोत से ली गई रकम पर ब्याज के भुगतान के लिए डीएसआरए (डेब्ट रिजर्व रेवेन्यू खाता) खोल रखा है। इस खाते में छह माह के ब्याज की रकम जमा है।